



International Journal of Advance Studies and Growth Evaluation

कमूलय आधारित शिक्षा के उद्देश्य

*¹ कमलेश कुमार चावले

*¹ सहायक प्राध्यापक—राजनीति विज्ञान, शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश, भारत।

Article Info.

E-ISSN: 2583-6528

Impact Factor (SJIF): 5.231

Available online:

www.alladvancejournal.com

Received: 21/July/2023

Accepted: 30/Aug/2023

सारांश

नैतिक मूल्य किसी व्यक्ति के अपने सिद्धांत अथवा गुण है, जो उसके निर्णय तथा व्यवहार को संचालित करते हैं। नैतिक मूल्य काफी कुछ जहाज के लंगर के समान हैं। जिस प्रकार एक जहाज तेज बहाव के आने पर भी लंगर के सहारे किनारे से लगा रहता है, उसी प्रकार उत्तम चरित्र और उच्चतर नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति विकट परिस्थिति अथवा दबाव में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। नैतिक मूल्यों का संबंध उन विचारों से हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। अर्थात् जो वांछनीय है, क्योंकि मानव जीवन में उनकी महत्ता है। किसी वस्तु या विचार को मूल्यवान कहने का अर्थ यह है कि वह वांछनीय है और वह वांछनीय इसलिए है क्योंकि उसकी महत्ता है और उसकी महत्ता इस तथ्य में है कि वह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक है अर्थात् उसके द्वारा हमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमारे व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य के साथ बनाई गई है। इस नीति में 21वीं सदी के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और पुनर्व्यवस्थापन के साथ ही भारतीय परंपरा एवं उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखने की भी बात की गई है। यह नीति इस सिद्धांत पर बनाई गई है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी ज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक मूल्यों के साथ सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

*Corresponding Author

कमलेश कुमार चावले

सहायक प्राध्यापक—राजनीति विज्ञान, शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश, भारत।

मुख्य शब्द: शिक्षा, मूल्य, नैतिकता, साक्षरता, व्यक्तित्व।

Introduction

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य व्यक्ति के आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। इसके पश्चात् 1986 में बनाई गई। इसमें 1992 में कुछ संशोधन भी किए गये किन्तु इसका भी ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केन्द्रित रहा। समय के साथ हमें यह महसूस हुआ कि 1986 की शिक्षा नीति में कुछ कमियां हैं इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है किन्तु यह ज्ञान उसे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नहीं बना पा रहा है।

अतः इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता पड़ी।

जब से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तब से शिक्षा पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा की व्याख्या की गई है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे 'शिक्षा' शब्द का अर्थ जानने की जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि यदि शिक्षा के मूल लक्ष्य को हम समझ जाते तो हमें लगता है कि आज कहीं शिक्षा दी ही नहीं जा रही है। आज जैसे धर्म का स्थान 'रिलिजन' ने ले लिया है वैसे ही शिक्षा का स्थान भी 'एजुकेशन' ने ले लिया है। जिसका एकमात्र लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है। अपना पेट भरने के लिए अपना जीवन किसी और के पास गिरवी रखकर पूरा जीवन दूसरे के अधीन व्यतीत करना हाक गया है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी केवल अपना पेट भरने के लिए शिक्षित होना चाहता है। माँ-बाप की जीवन भर की कमाई खर्चकर, अपने जीवन के

अमूल्य 20–25 वर्ष लगाकर अंत में पूरा जीवन किसी और का नौकर बनकर जीना चाहता है। जबकि वास्तविक शिक्षा स्वतंत्र रहकर जीना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना सिखाती है। शिक्षा या एजुकेशन में एक प्रमुख अंतर है कि हमारा देश पुरुषार्थ प्रधान जीवन शैली का समर्थक है। जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे बुद्धि, शरीर, मन और आत्मा के आध्यात्मिक रूप हैं। शिक्षा में ये चारों समाहित हैं। जबकि एजुकेशन में केवल अर्थ अर्थात् भौतिक पदार्थ की ही प्रधानता है, जिसका मुख्य लक्ष्य शारीरिक सुख मात्र है। इसी से हमारा मन (काम) भी संबंध रखता है। एजुकेशन में जीवन का अर्धांग (धर्म एवं मोक्ष) पूरा ही बाहर निकाल दिया गया है। अससे व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण संभव ही नहीं है। यह अपूर्णता ही एजुकेशन की मुख्य कमी है। आज व्यक्ति जितना उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, उतनी ही उसके व्यक्तित्व की अपूर्णता गहन होती जाती है और उसमें दया, करुणा और संवेदना के भाव कम होते जाते हैं। एजुकेशन का एक अन्य दुष्प्रभाव संयुक्त परिवारों का विघटन है, क्योंकि नौकरी करने के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है। संयुक्त परिवारों के विघटन का परिणाम संस्कारों की विलुप्ति के रूप में सामने आ रहा है। बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाय, इसकी जानकारी तो आधुनिक माता-पिता को है और न ही उनके पास बच्चों के लिए समय है। दादा-दादी के पास ज्ञान और समय दोनों हैं, लेकिन आधुनिक माता-पिता को उनपर विष्वास नहीं होता है। इन सब का परिणाम संस्कार विहीन समाज के रूप में हमारे सामने आ रहा है।

आज शिक्षा व्यवसाय और शिक्षक व्यवसायी बन गया है। और इस स्थिति में जब शिक्षक स्वयं व्यापारी, भ्रष्ट होकर विषयों का शोषण करने लगे तो शिक्षा की स्थिति का गिरना स्वाभाविक है। इसी कारण शिक्षा में राजनीति का प्रवेश हो जाता है। राजनीति के प्रवेश के साथ ही सत्ता बल, धन-बल, आकांक्षिता, हिंसा, कट्टरवाद आदि भी शैक्षणिक संस्थानों के अंग बनते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार सूचना है, इसमें जिसके पास सर्वाधिक सूचनाएं हैं वह ज्यादा शिक्षित है। लेकिन वह अपने स्वयं के बारे में सबसे कम जानता है। ठीक वैसे ही जैसे फेसबुक, ट्विटर पर हमारे मित्रो-फालोवरो की संख्या हजारों-लाखों में है, किन्तु वास्तविक जीवन में मित्रों की संख्या कम होती जा रही है। श्री इडियट, तारे जमीन पर जैसी फिल्में इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथ्यपुदा सिद्धांत देती है, लेकिन विचार उत्पन्न करने की क्षमता विकसित नहीं करती है। अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था उत्तर निर्भर है, प्रश्न निर्भर नहीं है। यह शिक्षा प्रणाली बोध स्मृति पर आधारित है और यह शिक्षा प्रणाली हमें पंडित तो बना सकती है किन्तु ज्ञानी नहीं। आज की शिक्षा विनयशीलता के स्थान पर अहंकार पैदा करती है। समाज में जिसे भी शिक्षित होने का अवसर मिला है, वे सभी अग्रेजीदा हो गए हैं। हमारा आज का समाज अनपढ़ों से कम और पढ़े-लिखे लोगों से ज्यादा त्रस्त है। सभी लोकसेवक सामान्य जनता के लिए पाषाण-हृदय हो गए हैं जिनका परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ रहा है। और भ्रष्टाचार की इस नाजायज संतान को पालने-पोषने में समाज का शिक्षित वर्ग ही अधिक जिम्मेदार है।

हमारी प्राचीन शिक्षा का सपना 'वासुधैव कुटुम्बकम्' रहा है। लेकिन एजुकेशन में व्यक्ति अकेला स्वयं के लिए जीना सीख रहा है। जैसा कि लोक प्रपासन के विद्वान डा. माहेश्वरी ने कहा है – "मैंने पढ़ाई के समय नैतिक शिक्षा पढ़ी, हमारे बेटे ने शारीरिक शिक्षा और हमारे पोते ने व्यावसायिक शिक्षा।" आज हमें फिर से नैतिक शिक्षा की ओर लौटना होगा। क्योंकि दो पीढ़ी के बाद देश में कोई समाज बचेगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। पश्चिम का उदाहरण हमारे सामने है। विज्ञान और धर्म दोनों ही आज अपूर्ण हैं। धर्म को शास्त्रों से बाहर लाना पड़ेगा और विज्ञान (शिक्षा) को भी जीवन के सभी पक्षों से जोड़ना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं विचारों को धरातल पर लाने का प्रयास है।

शिक्षा व्यवस्था को सफल नहीं बल्कि सफल मनुष्य की अवधारणा का विकास करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बुरे कामों में सफल

होने से अच्छा है कि वह अच्छे काम में असफल हो जाए। अभी भी शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन कर आज की प्राथमिकताओं के अनुरूप आमूल-चूल परिवर्तन करना अनिवार्य है। इसके लिये अब एकमात्र आस युवा पीढ़ी से बची है। वही शिक्षा की उपभोक्ता भी है और वही बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम भी है। उसको देश, समाज और स्वयं के सर्वांगीण विकास की आवश्यकताओं का पुनः आकलन करके क्रान्तिकारी कदम उठाने होंगे। युवाओं का लोकतंत्र के तीनों पायों (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका) को यह दृढ़ता से समझा देने की आवश्यकता है कि शिक्षा पहले व्यक्ति का चारित्रिक विकास करे, ताकि वह केवल पेट भरकर बिना कुछ किए अपना जीवन न व्यतीत करे।

व्यक्तित्व के विकास के दो आधारस्तंभ होते हैं – एक संस्कृति और दूसरी शिक्षा। जब आधार सही होगा तभी व्यक्तित्व का समग्र विकास संभव होगा, इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक था। स्वतंत्रता के समय हमें बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोलना हमारी प्राथमिक आवश्यकता थी। 1950 में देश में 20 विष्वविद्यालय थे, जिनकी संख्या अभी 943 हो गई है। जब इतना बड़ा मात्रात्मक वृद्धि होती है तो गुणात्मकता में कमी आना स्वाभाविक है। हम सभी अवगत हैं कि वर्तमान समय में हमारे मूल्यों का क्षरण हुआ है और इसका असर शिक्षा में भी देखने को मिल रहा है। वर्तमान में 93 प्रतिशत बी.एड. कॉलेज निजी हाथों में हैं। जबकि हमें शिक्षकों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना था जो हम नहीं दे पाए हैं इसीलिए बहुत सारे निजी बी.एड. कॉलेजों को अनुमति दे दी गई है और उसमें भी सीटें खाली रहती हैं। इसी तरह से जो खर्च कर सकते थे उन्होंने जब चाहा इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोल लिया। यह कमी देख ही नहीं गया कि वास्तव में राष्ट्र, देश या समाज को अब कितने इंजिनियरों, डाक्टरों या शिक्षकों की जरूरत है। किसी भी शिक्षा व्यवस्था का आधार षोडश है और षोडश जो कि किसी विष्वविद्यालय को नाम और पहचान देता है वह देश के कुछ अच्छे विष्वविद्यालयों को छोड़कर शेष विष्वविद्यालय नहीं कर पाए। विशेषकर राज्य विष्वविद्यालय जहां पर वित्त और शिक्षकों दोनों की कमी है। और यह मान्यता बन गई कि जो शिक्षक शोध नहीं करता वह अच्छा शिक्षक नहीं है। ये दोनों चीजें साथ-साथ चलती रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों में समन्वय की कमी की वजह से ऐसे विष्वविद्यालयों की घोषणा कर दी गई जो बाद में बजट की कमी से जूझते रहें। अभी हमारे नियमों में है कि हर प्राध्यापक को पी. एच.डी. करनी है, सेमिनार में जाना ही है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि पी.एच.डी. और सेमिनार का स्तर नीचे आया और यह एक तरह से तमाषा बन गया है। किसी भी दबाव में उच्च श्रेणी का शोध नहीं होता है, यह तभी संभव है जब शिक्षक स्वयं अपने मन से कार्य करता है। 1992 की उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। जब हमारी नीतियाँ इनके अनुरूप बनीं, तब बाजार शिक्षा पर हावी हो गया। इससे शिक्षा के मूल्य और गुणवत्ता दोनों समाप्त हो गए। शिक्षक जो हमारे लिए आदरणीय होता था, वह ऐसा हो गया जैसे जितनी तनखा मिलेगी, उसमें उतनी शिक्षा ले आएंगे और जितने पैसे हम दे पाएंगे वैसी शिक्षक (संविदा, अतिथि, नियुक्ति) हम ले आएंगे। इससे सच में शिक्षा का स्तर गिरा है और इसी कारण इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बी. एड. टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनते चले गए। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा युवा व्यक्ति को आनेवाले बदलावों को समझने और उसका विप्लेषण करने के लिए तैयार करती है। वह उसे योग्यता से सुसज्जित करती है, ताकि वह बदलाव का अंग बन सके और परिवर्तन का नेतृत्व कर सके। भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को सक्षम व कारगर बनने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि समाज द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसके कार्यों का पता लगाना मुश्किल नहीं है। अधिकांश संस्थानों की कार्य-संस्कृति पूर्ववत् है। स्कूलों का निष्पादन न के बराबर है तथा कॉलेजों में स्टाफ की कमी है। विष्वविद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं व नियमित फैकल्टी मੈम्बर के बिना अध्यापन कार्य चल रहे हैं। मूल्यों के चौतरफा ह्रास से

शिक्षा—व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित है। नई शिक्षा नीति में इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है।

निष्कर्ष

शिक्षा का उद्देश्य नैतिक मूल्यों से संपन्न मानव का निर्माण करना होना चाहिए। विवेकानंदजी का विचार था कि “विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से अतीत के प्रति सम्मान, वर्तमान की चुनौतियों एवं संबंधों के लिए सक्षम तथा भावी जीवन को सुखद एवं सुन्दर बनाने में समर्थ बनाना है।” पाठ्यक्रम सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए तथा वह व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सहायक होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को संस्कारों से जोड़ा तथा जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन के छः प्रमुख सिद्धांत सुनिश्चित किए – आत्मा की अमरता, विनम्रता का आचरण, माता-पिता एवं गुरुजनों के प्रति सदैव ऋणी रहना, जीवमात्र में ईश्वर के दर्शन कर सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना, जीवन के कर्तव्य का पालन करना और ईश्वर पर अटूट आस्था रखना। उन्होंने चरित्र निर्माण की महत्ता को समझाते हुए कहा – यदि आपने उत्तम विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन और चरित्र का आधार बना लिया, तो आप उस व्यक्ति से अधिक शिक्षित हैं जिसने सम्पूर्ण पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. अंजली भटनागर, “नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मानव जीवन दर्शन” राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, दिसंबर, 2022, 121–124.
2. डॉ. जी. आर. चौहान, “नई शिक्षा नीति-2020 एवं जीवन दर्शन” राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, दिसंबर, 2022, 44–45.
3. जे. एस. राजपूत, “क्या हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, जो बंधनों से मुक्त करती है?” समर्थ भारत, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 2009, 270–277.
4. एन. एन. ओझा, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि शब्दकोष, नई दिल्ली, कानिकल पब्लिकेशन, 2015, 94–132.
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020; 3:86-91.
6. करण सिंह, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप” लोक प्रशासन, मानवाधिकार एवं नई शिक्षा नीति, 2023, 108–112.
7. श्रीमति चंद्रकान्ता शर्मा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मातृभाषा में अर्जित ज्ञान की प्रासंगिकता” लोक प्रशासन, मानवाधिकार एवं नई शिक्षा नीति, 2023, 99–102.
8. डॉ. रत्नेश किशोर वर्मा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ” राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, दिसंबर, 2022, 09–13.
9. डॉ. सुखचैन सिंह धुर्वे, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक ” राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, दिसंबर, 2022, 45–47.
10. डॉ. नीलम चतुर्वेदी, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना ” राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, दिसंबर, 2022, 91.
11. दत्तात्रेय होसबोले “शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य और स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों की प्रासंगिकता” म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी व्याख्यानमाला श्रृंखला 2012/2, 2022, 01–13.